पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती • अब केवल मान्यता प्राप्त वेंडर्स को ही मिलेगा काम

महाराष्ट्र-गुजरात मॉडल पर बनेंगी सड़कें, तकनीक सीखने जाएंगे बिहार के इंजीनियर

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार की सड़कें अब अत्याधुनिक तकनीक से बनेंगी। इसके लिए राज्य के इंजीनियरों और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों में भेजा जाएगा। वे वहां आधुनिक प्रोजेक्ट्स की बारीकियां सीखेंगे और तकनीक आधारित विकास कार्यों को देखेंगे। ये घोषणा सोमवार को पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने पदभार संभालने के बाद की। उन्होंने माना कि बिहार जैसा राज्य अभी नई तकनीक के मामले में पीछे है, इसलिए पुल-सड़क समेत दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर मूर्तरूप देने के लिए इंजीनियरों को बाहर भेजना जरूरी है। मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। कहा कि निर्माण कार्यों में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को ही लगाया जाए। पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी अब केवल मान्यता प्राप्त वेंडर्स को ही मिलेगा। ताकि, काम ठीक से हो और उनकी जवाबदेही तय की जा सके।

मंत्री ने बिहार के कई बड़े एक्सप्रेस-वे और कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा भी की। इसमें दिल्ली-कोलकाता एनएच-19, ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर एनएच-27, पटना-गया-डोभी कॉरिडोर, आमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और पटना रिंग रोड शामिल हैं। इसके अलावा, छपरा-पटना-बख्तियारपुर-पूर्णिया और मोकामा-मिर्जा चौकी कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे बिना किसी दबाव और लालच के पूरी ईमानदारी से काम करें। बजट की समस्या नहीं है।

पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने पदभार संभाला, कहा- बजट की कमी नहीं

मैं खुद भी सिविल इंजीनियर हूं

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि वे खुद भी एक सिविल इंजीनियर हैं। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए सड़क मार्ग का सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए वे विकास कार्यों में अपनी इस दक्षता का पूरा इस्तेमाल करेंगे। वे विभागीय टीम के साथ एक-एक बात को सूक्ष्म तरीके से समझेंगे और फिर संवाद के आधार पर योजनाओं को लागू करेंगे। इसका फायदा विभाग को होगा। वे तकनीकी बारीकियों को समझकर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करा सकेंगे।

बिहार के ग्रीनफील्ड/एक्सप्रेसवे/कॉरिडोर प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट्स	लंबाई	लागत	अद्यतन स्थिति
1. आमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड	211	5604	निर्माणाधीन
2. पटना-गया-डोभी कॉरिडोर	131	1680	चालू
3. पटना रिंग रोड	107	10343	निर्माणाधीन
4. पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड	120	3712	शुरू नहीं
5. राम जानकी मार्ग	243	8060	निर्माणाधीन
6. मोकामा-मिर्जा चौकी	206	8330	शुरू नहीं
7. स्वर्णिम चतुर्भुज 6 लेन	220	3401	निर्माणाधीन
8. पटना-खगड़िया-पूर्णिया कॉरिडोर	167	4768	निर्माणाधीन
9. दानापुर-बिहटा-कोईलवर-बक्सर कॉरिडोर	118	3476	निर्माणाधीन
10. रजौली-बख्तियारपुर कॉरिडोर	105	3508	निर्माणाधीन
11. पटना-मानिकपुर-अरेराज-बेतिया	171	6867	निर्माणाधीन
12. पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे	282	18000	शुरू नहीं

बिहार से गुजरने वाले प्रोजेक्ट

1. गोरखपुर-सिलिगुड़ी ग्रीनफील्ड	416	23434	शुरू नहीं
2. वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड	158	5242	निर्माणाधीन
3. रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे	426	30000	शुरू नहीं

लंबाई किलोमीटर में और लागत करोड़ रुपए में

भास्कर एनालिसिस

तकनीकी अपग्रेडेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार

बिहार में सड़क और पुल निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बड़ा बदलाव आ सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में काफी आगे हैं। ऐसे में वहां की तकनीक अपनाकर बिहार अपने प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। मंत्री का खुद एक सिविल इंजीनियर होना इस विभाग के लिए प्लस प्वाइंट है। इससे तकनीकी खामियों को पकड़ना और ठेकेदारों की सीधे तौर पर जवाबदेही तय करना आसान हो जाएगा। पेटी कॉन्ट्रेक्टरों के लिए मान्यता की शर्त जोड़ने से निर्माण में लापरवाही पर लगाम लगेगी।